कंपनियों पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की बकाया राशि

1228.**श्री अनन्तराय जायसवाला** :

श्री सत्य प्रकाश मालवीय :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या यह सच हैं कि उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत परिषद का विभिन्न कंपनियो पर अरबों रूपये का बकाया हैं, यदि हां, तो किन-किन कंपनियों पर कितना-कितना रूपये बकाया हैं;

(ख) ऐसी कंपनियों में कितनी कंपनियां बन्द हैं और कितनी कंपनियां चालू हैं; और

(ग) क्या सरकार बकाया रकम को वसूल करने का विचार रखती हैं, यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध मे क्या कार्रवाई की गई हैं या की जा रही हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल) : (क) उ.प्र.रा.बि. बोर्ड ने सूचित किया हैं कि मार्च, 1995 के अंत तक अनेक कंपनियों/औद्योगिक उपभोक्ताओं की ओर उसकी 419.62 करोड़ रूपये की राशि 2284 कंपनियों की ओर बकाया हैं, जिनमें से प्रत्येक की ओर उ.प्र.रा.वि.वो. का एक लाख रूपये से अधिक बकाया हैं।

(ख) उ.प्र.रा.वि.बोड. के अनुसार उपर्युक्त पैराग्राफ (क) में उल्लिखित 2284 कंपनियों में से 1286 कंपनियां बंद हो चुकी हैं और 998 कंपनियों में से 1286 कंपनियों बंद हो चुकी हैं और 998 कंपनियां अभी कार्य कर रही हैं।

(ग) न्यायालय के स्थगन आदेशों के अनुसार रोकी गई राशियों को छोड़कर इन उपभोक्ताओं से बकाया देय राशियों की वसूली के लिए उ.प्रा.रा.वि. बोर्ड द्वारा की गई कार्रवाई में, अन्य बातों के साथ-साथ इन इकाइयों की विद्युत आपूर्ति काटना शामिल हैं।

Shifting of Dwarka TV Transmitter

1229. SHRIMATI ANANDIBEN JETHABAHI PATEL: Will the Minister of IFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether the shifting of Dwarka TV transmitter to some other place in Gu jarat is pending with Government for the last three years;

(b) if so, the action taken so far for shifting of this transmitter;

(c) the time schedule fixed for this purpose; and

(d) if not, the reasons and difficulties being faced by Government in its shifting?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI P.M. SAY-EED): (a) to (d) A new site for locating the High Power Transmitter at Dwarka has been taken over. The project is expected to be completed in about 3 years subject to availability of funds, infrastructure facilities and inter-se priorities. .

Cases Referred to BIFR

1230. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the number of cases of sick industrial units referred to Board for Industrial and Financial Reconstruction since 1992, year-wise;

(b) lime taken by the Board in giving its decision in each case referred to it; and

(c) whether Governments are aware of the need of reforming the functioning of the Board with a view to reduce the time taken in disposal of cases?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DE-BIPROSAD PAL): (a) The Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) has reported that the number of cases of sick industrial units received and registered by its since 1992, year-wise was as follows:

Year	No. of References Received	No. of Cases Registered
1992	225	177
1993	223	152
1994	296	193
1995	208	117
1996 (upto 31.01.1996)	22	10
Total	974	649